International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य

अनिल कुमार यादव
प्रवक्ता (भूगोल)
आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही गोरखपुर

आज, भारत दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश भी प्राप्त है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, हमें कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, अन्य देशों की तुलना में आज भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग आवश्यक कौशल में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति का अभाव है। भारत के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को न केवल युवाओं को विपणन योग्य कौशल से लैस करना चाहिए, बल्कि उन्हें रोजगारपरक बनाना चाहिए और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए या उद्यमिता का प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षा प्रणाली और उद्योग की आवश्यकता के आदानों के बीच एक कौशल अंतर मौजूद है। मेक इन इंडिया 'की दृष्टि ने पिछले वर्ष की तुलना में कौशल विकास को प्रमुख प्रोत्साहन दिया है। सरकार की योजना 2022 तक 150 मिलियन से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करने की है, जिसका अर्थ है कि अगले दस वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 45,000 युवाओं को कौशल प्रदान करना (* स्रोत: NSDC वेबसाइट)। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब उद्योग, शिक्षा और सरकार एक साथ आकर एक सुनहरा त्रिकोण तैयार करें।

कौशल विकास एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं है जिसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे ऐसे युवाओं के प्रशिक्षण और शिक्षा में एकीकृत करने की आवश्यकता है, जिन्हें देश के उद्योग को चलाने वाले तंत्र का हिस्सा बनने के लिए आसानी से रोजगार योग्य और सक्षम होना होगा। । इस राज्य में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) पर एक नज़र डालना फलदायी है। NSQF प्रत्येक योग्यता आधारित व्यावसायिक कौशल के लिए स्तरों और क्रेडिट को परिभाषित करता है। यह एक क्रेडिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए आगे बढ़ता है जो औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच मार्गों के निर्माण की अनुमति देता है। भारत में एनएसक्यूएफ को 27 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। एचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी एनवीईक्यूएफ (राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क) सहित अन्य सभी ढांचे, एनएसक्यूएफ द्वारा अलग किए गए हैं। NSQF के तहत, शिक्षार्थी औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर पर आवश्यक योग्यता के लिए प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। यह एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है।

शिक्षा की प्रक्रिया केवल किताबों को पचाने की नहीं है। यह कई सह-पाठयक्रम गतिविधियों को करने के बारे में भी है जो सामान्य रूप से जीवन और विशेष रूप से शिक्षा के लिए एक व्यापक अर्थ देते हैं। ऐसे समग्र विकास के अवसर भारत में पर्याप्त नहीं हैं। उसी के लिए सुविधाओं का अभाव है या भारत में आसानी से सुलभ नहीं है। यहां तक कि, जहां सुविधाएं मौजूद हैं, उसी के बारे में जानकारी का अभाव है। समुदाय आधारित कार्यक्रम होना चाहिए और सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता का तात्पर्य साझेदारी और पारस्परिकता के संदर्भ में ज्ञान और संसाधनों के पारस्परिक लाभकारी आदान-प्रदान के

लिए उच्च शिक्षा और उनके बड़े समुदायों के बीच सहयोग से है। संचार कौशल, समस्या को हल करने, इंटरैक्टिव कौशल, नागरिक जिम्मेदारियों को बढ़ाया जाता है जब छात्र समुदाय के लोगों की जीवन स्थितियों से परिचित हो जाते हैं।

भारत की विकास कहानी में, दुनिया का नंबर एक ज्ञान उत्पादन केंद्र बनना वैकल्पिक नहीं है। इसे पूरा करना अनिवार्य है क्योंकि जब तक 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ज्ञान का उत्पादन नहीं होगा, भारत कभी भी आर्थिक महाशक्ति नहीं बनेगा। तेजी से, आर्थिक विकास को सीधे तौर पर इस बात से जोड़ा जा रहा है कि इसके युवाओं को किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है।

भारत में कौशल विकास के संबंध में सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इसे परिभाषित किया जाए या इसे फिर से परिभाषित किया जाए। जबकि योजना आयोग, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा नीतिगत कागजात हैं, कौशल विकास क्या है और क्या होना चाहिए, इसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं है। वास्तव में, हमें अभी तक भारत में एक नीति दस्तावेज तैयार करना है जो युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने वाले कौशल को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। हमें अभी तक एक नीति दस्तावेज के साथ आना है जो कुछ पहलुओं और कौशलों में कौशल विकास की तात्कालिकता को परिभाषित करता है।

विश्व बैंक का सुझाव है कि न केवल ये सॉफ्ट स्किल्स महत्वपूर्ण हैं बल्कि आज ये 'श्रम उत्पादकता' के लिए महत्वपूर्ण हैं और नियोक्ता अपनी कंपनियों के लिए इन कौशल की तलाश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सॉफ्ट स्किल्स अलंकरण या संवारने वाले नहीं हैं क्योंकि भारत में कुछ लोग सुझाव दे सकते हैं लेकिन वे 'उच्च स्तर के संज्ञानात्मक कौशल' हैं,

भारत में एक कुशल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना

हमारी दृष्टि प्रमुख हितधारकों - उद्योग, प्रशिक्षण भागीदारों, शिक्षाविदों, प्रशिक्षुओं / छात्रों और सरकार के बीच बातचीत की सुविधा देकर लोगों को कौशल से जोड़ना है। वेबसाइट समाचार, कहानियों, घटनाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं, केस स्टडी, शोध रिपोर्टों को प्रस्तुत करती है जो शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को उलझाने, सक्षम और सशक्त बनाने की चुनौतियों को सामने लाती है। हम स्किलिंग और अपस्किलिंग के आकांक्षात्मक मूल्य के कारण से प्रेरित हैं और यह किसी के जीवन, समाज और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव ला सकता है।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) राष्ट्र की शिक्षा पहल का एक महत्वपूर्ण तत्व है जहां महत्वपूर्ण तत्वों को फिर से परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षण लचीला, समकालीन, प्रासंगिक, समावेशी और रचनात्मक हो।

भारत की जनसंख्या 1.267 बिलियन से अधिक है और 474.1 मिलियन का कार्यबल है, जिसमें से 336.9 मिलियन ग्रामीण श्रमिक हैं और 137.2 मिलियन 2011-12 में किए गए NSSO के अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार शहरी श्रमिक हैं। बेरोजगारी रजिस्टर में 2010 में 40.17 मिलियन पंजीकृत थे। सभी को बेरोजगारी दर के साथ 8.8 प्रतिशत पर सार्थक रोजगार प्रदान करना और हर साल लगभग 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती जनसंख्या वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जनसांख्यिकी के संदर्भ में, लगभग 35 प्रतिशत भारतीय

15 वर्ष से कम आयु के हैं, और लगभग 50 प्रतिशत 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। भारत की औसत आयु 24 वर्ष है, जो इसे शब्द में सबसे कम आबादी में से एक बनाती है।

"मेक इन इंडिया" और कौशल

प्रति वर्ष हजारों पीएचडी की आवश्यकता होती है लेकिन अनिवार्य अनुसंधान के साथ जो उद्योग को पहुंचाने में मदद करता है। एक स्पष्ट अनिवार्य शोध जो उद्योग को मदद करता है। सीएसआईआर / डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के लिए एक स्पष्ट अधिदेश, आईआईटी को ऐसे नवाचारों की आवश्यकता है जो रोजगार सृजन में सहायता करते हैं। उपरोक्त सभी संस्थानों में से प्रत्येक में कई आईपीआर-पेटेंट-उद्यमी कोशिकाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। यह अनुसंधान क्षमता के साथ-साथ राष्ट्रीय एजेंडा के साथ जोड़ता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, पावर, वाटर रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नैट टेक्नोलॉजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना प्राथमिकता पर अधिक होना चाहिए और सबसे अच्छा फंड प्राप्त करना चाहिए।

ऊर्जा, जैव-विज्ञान, जैव-इंजीनियरिंग और आनुवंशिकी में नवाचार के माध्यम से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना प्राथमिकता का अगला स्तर होना चाहिए। नवाचारों के प्रत्येक क्षेत्र में कई डाउनस्ट्रीम गतिविधियों को चलाया जाना चाहिए। नई सरकार के तहत आने वाले 100 मॉडल शहरों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वृद्धि और नए रोजगार बाजारों को बढ़ाने के लिए मास्टर स्ट्रोक है। यह बदले में कौशल बाजार को संशोधित करेगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन 15 जुलाई, 2015 को शुरू किया गया था, ताकि भारत भर में कौशल विकास के प्रयासों को तेजी से लागू किया जा सके।

मिशन स्टेटमेंट: 'भारत में कौशल विकास के प्रयासों को तेजी से बढ़ाने के लिए, एंड-टू-एंड, परिणाम-केंद्रित कार्यान्वयन ढांचा तैयार करके, जो स्थायी रूप से भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं के साथ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुशल कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं की मांगों को संरेखित करता है।

कौशल विकास के लिए एंड-टू-एंड कार्यान्वयन फ्रेमवर्क, जो जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं: स्कूली पाठ्यक्रम में स्किलिंग को शामिल करना, गुणवत्तापूर्ण दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, लाभप्रद रोजगार प्रदान करके और कैरियर पेशे को सुनिश्चित करना जो प्रशिक्षुओं की आकांक्षाओं को पूरा करता है। नियोजित-केंद्रित प्रशिक्षण के लिए एक रूपरेखा बनाकर, स्थायी आजीविका के लिए प्रशिक्षुओं की आकांक्षाओं के साथ नियोक्ता / उद्योग की मांग और कार्यबल उत्पादकता को संशोधित करें।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

कौशल विकास और उद्यमिता 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति

कौशल विकास और उद्यमिता 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति 2009 की नीति को प्रभावित करती है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य गति, मानक (गुणवत्ता) और स्थिरता के साथ स्केलिंग की चुनौती को पूरा करना है। इसका उद्देश्य देश के भीतर होने वाली सभी कौशल गतिविधियों के लिए एक छाता ढांचा प्रदान करना है, ताकि उन्हें सामान्य मानकों के साथ संरेखित किया जा सके और मांग केंद्रों के साथ कौशल को जोड़ा जा सके। उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों को निर्धारित करने के अलावा, नीति समग्र संस्थागत ढांचे की पहचान भी करती है जो अपेक्षित परिणामों तक पहुंचने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करेगा। कौशल विकास प्रमुख हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र, समुदाय आधारित संगठनों, उन उत्कृष्ट, उच्च योग्य और समर्पित व्यक्तियों के पूरे स्पेक्ट्रम जो कई वर्षों से उद्योग और व्यापार संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

कौशल विकास और आर्थिक प्रगति

कौशल विकास को प्रवीणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से हासिल या विकसित किया जाता है। वैश्विक नेताओं ने अपनी राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से कौशल विकास की भूमिका और प्रभाव को स्वीकार किया है। यह बाजार की बदलती माँगों के अनुकूल व्यक्तियों की क्षमता को मजबूत करता है और नवाचार और उद्यमशीलता गतिविधियों से लाभान्वित होता है। कौशल विकास के प्राथमिक निर्धारकों के अलावा, प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बदलती अर्थव्यवस्थाओं की नई मांगों को पूरा करने के लिए अवसरों और चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक है। देशों की भविष्य की समृद्धि आखिरकार रोजगार में व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है और वे काम पर कितने उत्पादक हैं। यह एक गतिशील परिदृश्य है जहां सबसे सफल या प्रगतिशील राष्ट्र एक होंगे जो VUCA (अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता, अस्पष्टता) (Abidi & Joshi, 2015) का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए, कौशल विकास को व्यापक विकास, रोजगार और सरकार के हस्तक्षेप के विकास से जोड़ा जा सकता है।

शिक्षित और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता

एक बेहतर शैक्षिक शासन के लिए व्यापक सिद्धांतों को गुणवत्ता के बेहतर विनियमन के साथ करना है, प्रोत्साहन जो गठबंधन किए गए हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जहां शिक्षित और कुशल श्रमिकों की तैयारी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है। शिक्षा के विभिन्न चरणों में शिक्षा प्रणाली का सामना करने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं। स्कूल शुरू करने वाले लगभग ३५ प्रतिशत छात्र १० में से १० लाख परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, १० में से १० वीं कक्षा पास नहीं करते हैं। 16 मिलियन में से आठ जो ग्रेड 12 परीक्षाओं को नहीं लेते हैं, उन्हें पास करने में असफल होते हैं। 8 मिलियन में से केवल 5 मिलियन जो सफलतापूर्वक 12 वीं कक्षा की पिछली परीक्षाओं में कॉलेज जाते हैं। शिक्षित और कुशल श्रमिकों और पेशेवरों के एक मजबूत पूल को तैयार करने के लिए शिक्षा के निचले स्तरों पर रेटेड सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

भारत में वैश्वीकरण और व्यापार उदारीकरण ने भारत के श्रम बाजार में कई बदलाव किए हैं। प्रत्यक्ष परिणाम प्रौद्योगिकी की आमद है, आर्थिक सुधारों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, और एक कौशल-आधारित कार्यबल के विकास पर इसका प्रभाव, अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे उद्यमों के लिए भी अवसर की एक पूरी नई खिड़की खोल रहा है। कौशल मानव पूंजी को बेहतर बनाने की एक विधि है, जो श्रमिकों को आय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में खराब शिक्षित श्रमिकों के लिए, और इसलिए इस विशाल कार्यबल को समृद्ध करने की एक कुंजी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाजार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। कार्यबल के अनौपचारिक खंड को कई सामान्य विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है: सीमित पेशेवर कौशल, कम आय, कम उत्पादकता और कम पूंजी निवेश पर। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से नए विपणन योग्य रोजगार कौशल विकसित करना अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और श्रमिकों के औपचारिक-क्षेत्र रोजगार में उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके चक्रीय गरीबी को बाधित कर सकता है। इस प्रकार, इस समूह को उनकी उत्पादकता का अनुकूलन करने और राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है।

References

- Aggarwal, J. (2009). *Recent Developments and Trends in Education* (third edition). Delhi : Shipra Publications.
- Broadfoot, P. 1996, Education, Assessment and Society: A Sociological Analysis, Open University Press, Buckingham.
- DGET (Various Years). Annual Report. Report of the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, India.
- Bhushan, S. (2009). *Restructuring Higher Education in India.* Jaipur: Rawat Publications.
- Eleventh Five Year Plan, Volume I, II and III, Planning Commission, New Delhi, December 2007.
- Krishnan, K.P. & Nambiar, D. (2017, September 2-8). Skill India: Challenges, Achievements and the Way Forward, *Employment News* (2018, Aug. 3).
- Tenth Five Year Plan Document, Planning Commission, New Delhi, December 2002.
- DGE&T (2008), Annual Report, Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi
- GoI (2009), National Policy on Skill Development, Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi

- ILO (2003), Industrial Training Institutes of India: The Efficiency Study Report, Geneva India Labour Report 2008
- World Bank (2006), Skill Development in India – The Vocational Education and Training System, Human Development Unit, South Asia Region, January 2006